



खबर नहीं, खबरों के पीछे की खबर

रेड रोज न्यूज़

दिल्ली से प्रकाशित राष्ट्रीय हिंदी मासिक समाचार पत्र

वर्ष : 18 अंक : 3

नई दिल्ली मार्च 2025

कुल पृष्ठ : 8

मूल्य : 2/ रुपये

Regd. RNI No : DELHIN/2007/21149

संक्षिप्त सार

ट्रक के नीचे घुसी कार, महिला समेत चार की मौत, एक गंभीर

महोबा (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में एक तेज रफ्तार कार ट्रक के नीचे घुस गई। इस भीषण हादसे में तीन लोगों की मौत पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दो लोग घायल हुए थे। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान एक अन्य महिला की मौत हो गई। वहीं, दूसरे घायल का उपचार जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक, जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था वह ऑल्टो कार है। ऑल्टो सवार सभी लोग प्रयागराज से भोपाल लौट रहे थे। तभी हाईवे पर बड़ा नाला के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे के बाद ट्रक ऑल्टो कार को 50 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। कार और ट्रक की इस भीषण टक्कर के बाद कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवागमन लगभग एक घंटे तक बाधित रहा, जिससे जाम की स्थिति हो गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में फंसी ऑल्टो को जेसीबी की मदद से बाहर निकलवाया। फिर धीरे-धीरे यातायात को बहाल किया गया। मृतकों की पहचान नरेश नागर पुत्र सिद्धनाथ, अवधेश नागर पुत्र बाबूलाल व भूरा गुर्जर के रूप में हुई है। वहीं, पूजा नागर पुत्री अनूप सिंह का इलाज अस्पताल में जारी है।

नेपाल में कांपी धरती, भूकंप के झटकों से सहमे लोग, रिक्टर स्केल पर 6.1 रही तीव्रता

काठमांडू (एजेंसी)। शुक्रवार को सुबह नेपाल में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया जिससे हिमालय क्षेत्र में कंपन महसूस किया गया। पटना और बिहार के आस-पास के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, भूकंप नेपाल के सिन्धुपाल्चोक जिले के भैरव कुंडा के आसपास सुबह करीब 2.35 बजे आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज ने भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी, जबकि भारत के नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने इसकी तीव्रता 5.5 आंकी। हालांकि, यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या कई भूकंप आए थे। 6.1 तीव्रता का भूकंप शक्तिशाली माना जाता है और इससे काफी नुकसान हो सकता है, खास तौर पर भूकंप के केंद्र के पास, जिसमें इमारतें हिलना और दरारें पड़ना शामिल है। शुक्रवार की भूकंपीय गतिविधि की सीमा का अभी पता नहीं चल पाया है।

उत्तराखंड में एवलांच, 57 मजदूर दबे, 16 का रेस्क्यू, बद्दीनाथ हाईवे पर बर्फ हटाने के काम में लगे थे, 4 गंभीर

चमोली (एजेंसी)। उत्तराखंड के चमोली में शुक्रवार सुबह 7.15 बजे एवलांच की वजह से 57 मजदूर बर्फ में दब गए। मजदूर 8 कंटेनर और एक शेड में थे। घटना बद्दीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माणा गांव में हुई। यहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन (बीआरओ) की टीम चमोली-बद्दीनाथ हाईवे पर बर्फ हटाने के काम में लगी हुई है। मजदूर बीआरओ की टीम के साथ थे। सेना के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही क्विक रिस्पॉन्स टीम के 100 से ज्यादा जवान तत्काल रेस्क्यू में जुटे। इसमें डॉक्टर, एम्बुलेंस स्टाफ भी शामिल हैं। सुबह 11.50 बजे टीम ने 5 कंटेनरों का पता लगाया और 10 मजदूरों को निकाला। इन लोगों को जोशीमठ और माणा के अस्पतालों में भेजा गया है। 10 में से 4 की हालत गंभीर है। सेना के मुताबिक 3 कंटेनरों की तलाश जारी है। अबतक कुल 16 मजदूरों का रेस्क्यू किया जा चुका है। 41 की तलाश जारी है। सेना के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीमों मौके पर मौजूद हैं। हेलिकॉप्टर और ड्रोन टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। हादसे को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ बैठक की है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने घटना को लेकर उत्तराखंड के सीएम, सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के अधिकारियों से बातचीत की है। माणा तिब्बत



सीमा पर भारत का आखिरी गांव है। इधर, मौसम विभाग ने 28 फरवरी की देर रात तक उत्तराखंड में भारी बारिश का

अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 20 से 0 मि तक बारिश हो सकती है। चमोली कड संदीप

कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल का पंजाब दौरा, गोल्डन टेंपल में टेका माथा कहा केजरीवाल सत्ता लोभी

अमृतसर (एजेंसी)। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी नियुक्त होने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली बार प्रदेश के दौरे पर आ गए हैं। इस दौरे को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अमृतसर पहुंचने पर पंजाब के सभी सीनियर नेताओं ने उनका स्वागत किया। रोड शो निकाला जा रहा है, जिसमें भूपेश बघेल का जगह-जगह स्वागत किया जा रहा है। गोल्डन टेंपल में माथा टेकने के बाद भूपेश बघेल ने आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर निशाना

साधा है। उन्होंने कहा केजरीवाल को सिर्फ सत्ता का लोभ है। एक महीना भी दिल्ली चुनाव हारे नहीं हुआ और वे राज्यसभा जाने की सोच रहे हैं। वे सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं।

पिछले उपचुनाव और नगर निगम चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस 2027 में वापसी की उम्मीद कर रही है। बघेल शुक्रवार को अमृतसर के बाद



शनिवार को चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। यहां वह शनिवार पंजाब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे।



विश्वजीत शर्मा (चेयरमैन)

रेड रोज न्यूज की तरफ से देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं



विशाल शर्मा (डाइरेक्टर)

रेड रोज न्यूज की तरफ से देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

सम्पादकीय

कामयाबी का जनोत्सव

सरकारी आंकड़ों पर विश्वास करें तो इस महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों ने गंगा-यमुना व अदृश्य सरस्वती के संगम पर महाकुंभ के दौरान डुबकी लगायी। एक भगदड़ की घटना में कुछ श्रद्धालुओं का असमय काल-कवलित होना दुखद ही था। कुछ अग्निकांड भी हुए। लेकिन यदि बात करोड़ों श्रद्धालुओं के संगम में स्नान व उनके आने-जाने व रहने की व्यवस्था की हो तो योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। रूस-अमेरिका जैसी महाशक्तियों की आबादी से अधिक जनसंख्या का प्रबंधन निश्चय ही एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे दौर में जब उपभोक्ता संस्कृति सिर चढ़कर बोल रही है, तब सनातन संस्कृति का ऐसा उफान चौंकाता है। जिसमें लोग तमाम कष्ट सहकर संगम में डुबकी लगाने को आतुर दिखे। त्याग-संयम से परिचित कराना कुंभ संस्कृति का उद्देश्य भी रहा है। इस तरह हमने अपने पुरखों की गौरवशाली विरासत का सम्मान किया। जिसमें सदियों से करोड़ों लोग बिना चिढ़ी-पत्री के स्वरूपस्फूर्त भाव से कुंभ के मेले में जुटते रहे हैं। भारतीय संस्कृति में ऐसी क्या खासियत है? महाकुंभ जैसे इतने बड़े आयोजन कैसे सफलतापूर्वक होते हैं? यह देखने पूरी दुनिया के जिज्ञासु, विभिन्न धर्मों के अनुयायी, फोटोग्राफर और पत्रकार सदियों से महाकुंभ में जुटते रहे हैं। महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को युग-परिवर्तन की आहट और विशाल आयोजन की क्षमता से रूबरू कराया है। महत्वपूर्ण यह है कि तीर्थयात्रियों ने जिस तरह दिल खोल कर खर्च किया, वो निश्चय ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का तारणहार बनेगा। बताते हैं कि इससे प्रदेश की जीडीपी में करीब साढ़े चार लाख करोड़ रुपये का इजाफा होगा। जो देश की तमाम देशी-विदेशी इनवेस्ट समिटों से कहीं ज्यादा ठोस आय का स्रोत बना है। कई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस महाकुंभ के नाम हुए। वीरवार को तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री योगी को सौंपे गए। विपक्ष, खासकर सपा व कांग्रेस कुंभ आयोजन को लेकर हमलावर रहे हैं। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने महाकुंभ के समापन पर कहा कि ये सरकारी महाकुंभ है। असली कुंभ तो माघ पूर्णिमा को ही संपन्न हो चुका था। इस बार के महाकुंभ को टेक्नोलॉजी के महाकुंभ के रूप में भी याद किया जाएगा। महाकुंभ में विशेष एल्गोरिदम के जरिये इस्तेमाल पांच सौ एआई कैमरे क्राउड डेंसिटी व फैंशियल रिकग्निशन के लिये इस्तेमाल किए गए। जिसके जरिये करोड़ों श्रद्धालुओं की गिनती संभव हुई। वहीं बिछुड़ों को परिजनों से मिलाने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। निस्संदेह, इतने बड़े जनसैलाब को संभालना किसी भी सरकार के लिये बड़ी चुनौती होती है। लेकिन भविष्य में महाकुंभ के आयोजन के लिये प्रयागराज महाकुंभ के अनुभवों से सबक लेने की जरूरत है। इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए कि भगदड़ को कैसे टाला जाए। आखिर क्यों दो सौ- तीन सौ किलोमीटर के जाम लगते रहे हैं। कैसे ट्रेनों का संचालन बिना किसी व्यवधान के किया जाए। हालांकि, 16 नई ट्रेनें चलाने की बात कही गई, लेकिन तमाम स्टेशनों पर ट्रेन में चढ़ने के लिये मारामारी होती रही है। दिल्ली रेलवे स्टेशन का हादसा इसका ज्वलंत उदाहरण है। महाकुंभ के सफल आयोजन ने बताया है कि देश में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।

नई राजनीति की जरूरत, पुराने चेहरों का बोझ

अरविन्द मोहन
आखिरकार निशांत कुमार का बयान भी आ गया कि एनडीए को चाहिए कि नीतीश को कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने की घोषणा कर दे। निशांत माने नीतीश कुमार के पुत्र। पहली बार सार्वजनिक रूप से ऐसा बयान देकर उन्होंने कई तरह के संकेत दिए। निश्चित रूप से पहला संकेत तो राजनीति में आने का है। बीते बीस साल से मुख्यमंत्री के संग रहने और अकेली संतान होने के चलते सारा लाड़-प्यार पाने के बावजूद अभी तक उनके किसी आचरण को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं थी। बल्कि वे इतने शांत और सावधान तरीके से रहते थे कि काफी सारे राजनैतिक पंडित उनके सामान्य होने पर ही शक करते थे। अब अगर वे बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद और पचास साल की उम्र में और पार्टी तथा समाज के अनेक पक्षों से बार-बार की जा रही मांग के बाद सक्रिय होने का फैसला करते हैं तो उन्हें शुभकामना दी जा सकती है। अपनी स्वर्गवासी मां के जन्मदिन पर आयोजित किसी कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही और जदयू का प्रदर्शन पहले से बेहतर होने की बात भी कही। यह संयोग है कि उनका कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने बिहार दौरे में नीतीश जी को श्लाङ्गला मुख्यमंत्री श्र बताने के दो दिन बाद

ही हुआ। प्रधानमंत्री ने इस दौरे के साथ ही भाजपा और एनडीए के चुनाव अभियान का शंखनाद भी कर दिया। इसमें की लोगों को पांच साल पहले बीच कोरोना में हजारों रंगीन टीवी सेट के माध्यम से बिहार में आनलाइन शंखनाद करने वाला प्रसंग भी याद आया क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक साथ बिहार के सारे कोनों को छू लिया था। उन्होंने नीतीश जी को आगे रखकर चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की। शायद उनके पास ऐसा कोई और नाम है भी नहीं। लेकिन बीते साल भर में एनडीए और भाजपा की तरफ से यह कहा जाता रहा है। कमाल यह है कि इसके बावजूद निशांत कुमार को यह बात दोहराने की जरूरत हुई। बीते दो-तीन महीनों में विपक्षी राजद की तरफ से नीतीश कुमार के एक बार फिर से पाला बदलने की बात उछाली जा रही है और लालू प्रसाद यादव ने अब भी नीतीश का स्वागत करने की बात भी चला दी है। खुद नीतीश कुमार भी इस सवाल पर अपने ही आचरणों से संदेह गहरा रहे हैं। दिल्ली के अपने दो दौरों में उन्होंने भाजपा के किसी नेता से भेंट नहीं की या भाजपा के शीर्ष नेताओं ने उन्हें समय न दिया। वे दिल्ली में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण में भी नहीं थे जबकि एनडीए के बाकी सभी मुख्यमंत्री थे। उससे भी ज्यादा चर्चा उनकी पार्टी के दो बड़े नेताओं का दिल्ली

शशिकान्त पाण्डेय
ये हैं तो दो अलग-अलग परिघटनाएं जिनका एक-दूसरे से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं दिखता, परन्तु दोनों से ही दक्षिणपंथियों की विचारधारा और सरकार की कार्यपद्धति का पता चलता है। एक का सम्बन्ध विनायक दामोदर सावरकर के वंशजों से है तो दूसरा एक ऐसे डीन की नियुक्ति के बाबत है जो महात्मा गांधी के हत्यारे पर गर्व करती है तथा उसे देश को बचाने वाला मानती है। दोनों घटनाएं यह भी बतलाती हैं कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के निजी प्रयासों तथा राज्य-समर्थित सांस्थानिक कृत्यों द्वारा भारत को किस दिशा में ले जाया जा रहा है।

पहले बात करें अंग्रेजों की जेल से माफी मांगकर छूटने वाले सावरकर की! कांग्रेस राहुल गांधी ने मार्च, 2023 में लंदन में एक भाषण के दौरान बतलाया था कि सावरकर ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर कथित तौर पर श्मले को आनंददायक कहा था। इसे लेकर उनके वंशजों में से एक सात्यकि अशोक सावरकर ने पुणे की विशेष सांसद-विधायक कोर्ट में राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। 19 फरवरी को इसकी पेशी थी लेकिन राहुल को अदालत ने उपस्थिति की छूट दी थीय परन्तु अब उन्होंने मामले की सुनवाई श्मसरी ट्रायलश की बजाये श्मसन ट्रायलश के रूप में करने की मांग की है ताकि वे सावरकर से सम्बन्धित ऐतिहासिक सबूत एवं दस्तावेज रिकॉर्ड के लिये पेश कर सकें। लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ मामला दायर करने वाले सात्यकि ही नहीं बल्कि सावरकर के परिवार एवं उनकी विचारधारा को मानने वाले सभी व्यक्तियों-संगठनों के लिये यह परेशान होने का पर्याप्त कारण है क्योंकि इस सच्चाई से वे स्वयं भी अवगत हैं कि सावरकर को जब अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर (अंडमान-निकोबार) की सेलुलर जेल में कालेपानी की सजा देकर रखा था तब उन्होंने छूटने के लिये लगभग एक दर्जन माफीनामे लिखे थे। इतना ही नहीं, रिहा

होने के बाद उन्हें अंग्रेजों द्वारा हर माह 60 रुपये की पेंशन भी दी जाती थी। इसे भी बढ़ाने की वे दरखास्त करते रहे। इसके बाद वे जब तक जीवित रहे, उन्होंने कभी भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मुंह नहीं खोला था।

सावरकर को लेकर तभी से विवाद जारी हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में बनी है। पूरी भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं अन्य सहयोगी संगठन सावरकर का महिमा मंडन करते नहीं अघाते, बावजूद इसके कि कई मुद्दों पर उनके विचार अलग थे। मसलन, सावरकर गाय को अन्य पशुओं की ही तरह मानते थे। आजादी के बाद निष्क्रिय जीवन बिताने वाले सावरकर को लोगों ने एक तरह से भुला दिया था। थोड़े से लोग हैं जो उन्हें वीर या श्कांतिकारीश जैसे शब्दों से नवाजा करते हैं। जब उनके चरित्र को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना शुरू किया गया तो दूसरी ओर उनकी असलियत भी सामने आने लगी। अधिकतर लोगों को उनके माफीनामे तथा पेंशन के बाबत भी इसी दौरान ज्ञात हुआ। उनका कृत्रिम आभासंडल अज्ञात, अल्पज्ञात या छिपाये गये तथ्यों के सामने आने से ध्वस्त हो गया। इसलिये सावरकर परिवार नहीं चाहता कि राहुल गांधी अपने बचाव में वे सारे ऐतिहासिक तथ्य कोर्ट के सामने रख दें जो संग्रहालयों, लाइब्रेरियों, शोध ग्रंथों, लेखों, इतिहास की किताबों आदि में दर्ज हैं। सावरकर परिवार के लिये उन्हें नकारना मुश्किल होगा क्योंकि जवाब में उन्हें वे तथ्य झूठे साबित करने होंगे जो कि सम्भव नहीं है। खतरा यह है कि थोड़े-बहुत लोग जो वस्तुस्थिति से नावाकफि हैं, वे भी अवगत हो जायेंगे। इसलिये समन ट्रायल का विरोध जायज है। उनके वकील एसए कोल्हटकर ने कहा कि राहुल मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं ताकि मामला खींचा जा सके। उन्होंने ध्यान दिलाया कि कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि के कई मामले चल रहे हैं। दरअसल वे बतलाना चाहते हैं कि लोगों का अपमान करने के राहुल आदी हैं। वैसे

तो इन दोनों ही तर्कों में कोई दम नहीं है क्योंकि भारतीय न्यायालयों की धीमी प्रक्रिया सर्वविदित है। जिन मामलों का उल्लेख एड. कोल्हटकर कर रहे हैं, वे लगभग सारे लम्बित हैं। सिर्फ गुजरात की एक कोर्ट में मोदी समुदाय के कथित मानहानि वाले मामले में निचली अदालत में आनन-फानन में फैसला सुनाया था जिससे राहुल की लोकसभा (पिछली) की सदस्यता छीनी गयी थी (जो सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुई थी)। वह कार्रवाई राजनीतिक कारणों से हुई थी क्योंकि राहुल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कारोबारी मित्र गौतम अदानी के खिलाफ हमलावर थे। राहुल-सावरकर मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। सावरकर का विरोध राहुल की वैचारिक लड़ाई का हिस्सा है। जिस महाराष्ट्र में सावरकर के सबसे ज्यादा समर्थक हैं और शिवसेना का उद्भव ठाकरे के नेतृत्व वाला धड़ा उनका सहयोगी है, उसी जमीन पर चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने कहा था कि मानहानि के मामले में वे माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि वे सावरकर नहीं हैं। वैसे तो भाजपा तथा संघ ने सावरकर को वैसी तवज्जो कभी नहीं दी थी जो अब दी जा रही है। इसका कारण गांधी-विरोध ही है। सावरकर भी गांधी हत्या कांड में संदिग्ध आरोपी थे। हालांकि वे सबूतों के अभाव में छूट गये थे। तो भी गांधी-नेहरु से भाजपा-संघ की घृणा का आयाम विस्तृत है। इसी की श्रृंखला में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), कालीकट के योजना व विकास विभाग की नयी डीन के रूप में उन डॉ. शैजा अंदावन को नियुक्त किया गया है जिन्होंने गांधी पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी कि श् उन्हें गोडसे पर गर्व है जिन्होंने भारत को बचा लिया। हालांकि लोगों के विरोध के बाद उन्होंने उस पोस्ट को डिलीट तो कर दिया था पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी और वे अभी जमानत पर हैं। अब उनकी नियुक्ति पर मुहर लगाकर केन्द्र सरकार ने साबित कर दिया है कि उसकी सोच गांधी को लेकर क्या है।



आकर पूरी तरह भाजपा के रंग में रंगना है और इसे ही राजनैतिक पंडित नीतीश कुमार की घेराबंदी बताते हैं। नीतीश बिहार में भी भाजपा के एक गुट के व्यवहार को लेकर बहुत प्रसन्न नहीं रहते। यह समूह भाजपा के अकेले चुनाव लड़ने की वकालत भी करता है। यह अटकल भी लगती है कि चुनाव तक भाजपा उनको आगे रखकर बाद में कोई और पद या जिम्मा दे देगी। नीतीश और उनके समर्थक यह नहीं चाहते। अब जाने अनजाने भाजपा का समर्थन आधार बढ़ता गया है लेकिन अगड़ों को छोड़कर कोई और सामाजिक समूह पक्का समर्थक नहीं है-बीच के प्रयास नीतीश मामले में हाँ-ना के चक्कर में खिसक गया है।

इसलिए निशांत के बयान का एक तीसरा मतलब भाजपा के संग अपनी पार्टी के अगड़े नेताओं के लिए भी है जिनकी भाजपा से नजदीकी जगजाहिर है। यही लोग नीतीश कुमार के पाला बदलकर भाजपा के संग आने का माध्यम भी बने थे और अभी दिल्ली में जमे हैं। भाजपा को भी इस बयान का मतलब यह निकालना चाहिए कि नीतीश कुमार ललन सिंह, विजय चौधरी और संजय झा जैसे के समांतर किसी अपने और ज्यादा भरोसेमंद को खड़ा करना चाहते हैं। निशांत पिता की इच्छा देखकर ही पंख फैलाना शुरू कर रहे हैं। इस क्रम में आईएस रामचन्द्र प्रसाद सिंह का प्रसंग याद करना चाहिए जो ज्यादा पंख फैलाकर

झुलस चुके हैं। जब वे नीतीश जी के साथ थे तो बिना राजनैतिक पृष्ठभूमि के भी सबसे भरोसेमंद थे। दूसरी ओर, कांग्रेस और राजद के रिश्ते एनडीए के घटकों से भी ज्यादा खराब हैं। हरियाणा का चुनाव हारने के बाद तो अखिलेश और तेजस्वी का रुख भी बदला। दिल्ली चुनाव ने दूरी और बढ़ाई और अब तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भाजपा की तरह कांग्रेस में भी कुछ लोग अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने की वकालत कर रहे हैं। कांग्रेस का भी आधार या स्वीकृति बढ़ी है लेकिन कोई एक या दो ठोस सामाजिक आधार नहीं है। मुसलमान समर्थक हैं लेकिन राजद साथ न हो तो उनका वोट मिलने का भरोसा नहीं है। संगठन कमजोर है और अगर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जैसे उत्साही उसके पास हैं तो लालू-तेजस्वी उनको जमीन देने को तैयार नहीं हैं। लालू जी ने पिछले लोकसभा चुनाव में अहीरों को काम टिकट, कोइरी समाज को ज्यादा टिकट और वाम दलों समेत सारे विरोधियों को साथ लेकर अच्छी टक्कर दी लेकिन पहले दो राउंड के बाद भाजपा फिर से जंगल राज का शोर मचाकर बाजी पलट दी। इस बार यह शोर पहले से मच रहा है।

वोकल फॉर लोकल अभियान अब रंग ला रहा, भारत दुनिया के कारखाने के रूप में उभर रहा : पीएम मोदी

नयी दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को कहा कि उनका “वोकल फॉर लोकल अभियान अब रंग ला रहा है क्योंकि भारतीय उत्पाद वैश्विक हो रहे हैं और दुनिया भर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। मोदी ने ‘एनएक्सटी सम्मेलन में ‘न्यूजएक्स वर्ल्ड चैनल के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि दुनिया दशकों तक भारत को अपने ‘बैक ऑफिस के रूप में देखती रही, लेकिन देश अब दुनिया के कारखाने के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भारत कार्यबल नहीं बल्कि एक “विश्व शक्ति है। पीएम मोदी ने कहा कि देश ‘सेमीकंडक्टर और विमानवाहक पोत बना रहा है तथा इसके मखाना और बाजरा जैसे ‘सुपरफूड (न्यूनतम कैलोरी और अधिकतम पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थ), आयुष उत्पाद तथा योग को दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक प्रमुख ऑटोमोबाइल उत्पादक बन गया है और इसका रक्षा निर्यात बढ़ रहा है।



मोदी ने कहा कि भारत को बिना किसी लीपा-पोती के वैसा ही पेश किया जाना चाहिए जैसा वह है। उन्होंने कहा कि इसे किसी तरह के दिखावे की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की असली कहानियां दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का तीसरी बार फिर से चुना

जाना लोगों के भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत का नया वैश्विक समाचार चैनल देश की उपलब्धियों को विदेशों तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया 21वीं सदी में भारत की ओर देख रही है और देश लगातार सकारात्मक खबरें पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अब कई वैश्विक पहलों का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने हाल में एआई (कृत्रिम मेधा)

छोटे निवेशकों के हित में पारदर्शी बाजार नियामक जरूरी : राहुल गांधी

नयी दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड गिरावट के कारण मचे कोहराम पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि छोटे निवेशकों के हित के लिए वर्तमान माहौल में पारदर्शी बाजार नियामक व्यवस्था की सख्त जरूरत है।

राहुल ने शनिवार को कहा कि शेयर बाजार में भूचाल आया हुआ है और ऐसी स्थिति में छोटे निवेशकों को हो रहा नुकसान उनके लिए चिंता का विषय बन गया है। उनका कहना है कि खुदरा निवेशकों की सुरक्षा को जरूरी बताते हुए कहा कि इसके लिए पारदर्शी निवेदक व्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने कहा, “जब-जब बाजार गिरता है, खुदरा



निवेशक का ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मेरे लिए मध्यमवर्ग से आने वाले इन खुदरा निवेशकों के बचत,

हितों और निवेश की रक्षा करना सबसे अहम है—और इसके लिए सबसे जरूरी है पारदर्शी बाजार नियामक।”

काम में लापरवाह कर्मचारियों को सरकार करेगी जबरन रिटायर, सीएम ने दिए विधिवत करने के निर्देश

देहरादून (संवाददाता)। सरकारी काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को धामी सरकार जबरन रिटायर करेगी। शुक्रवार को उच्चाधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित करने के निर्देश दिए जो अपने दायित्व का भली भांति निर्वहन नहीं करते हैं।

मुख्यमंत्री आवास में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कार्य संस्कृति में और अधिक सुधार लाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दायित्व का कायदे से पालन न करने वाले कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रदेश में सरकारी भूमि और कई मामलों में लोगों की व्यक्तिगत भूमि पर कब्जा करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने को कहा।

उन्होंने कहा कि विभिन्न अपराधों में



लिप्त वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस विशेष अभियान चलाए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में और प्रयास किए जाएं। इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, बार्बर, प्लंबर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के प्रशिक्षण और कौशल विकास की दिशा में कार्य किए जाएं।

बैठक में सचिव गृह शैलेश बगोली, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव एवं गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

मिलावटखोरों व बिजली चोरों के खिलाफ चलाए सघन अभियान मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारों के

शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी और जी-20 की भारत की अध्यक्षता का जिक्र किया। पीएम मोदी ने महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि इसने कार्यक्रमों का आयोजन करने के भारत के कौशल और नवोन्मेष को उजागर किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कई अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के एक कानून के तहत 10 या उससे अधिक लोगों के नृत्य करने को अपराध माना गया था और यह कानून तब तक लागू रहा जब तक कि उनकी सरकार ने इसे निरस्त नहीं कर दिया। प्रधानमंत्री ने “लुटियन जमात और “जनहित याचिका के ठेकेदारश्श पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे हर चीज के लिए अदालत जाते हैं, लेकिन ऐसे कानून पर चुप्पी साधे रहते हैं। उन्होंने कहा कि तब वे आजादी के बारे में नहीं सोचते थे।

9.61 लाख करोड़ स्वाहा... शेयर बाजार में टूट गया 28 साल का रेकॉर्ड, संसेक्स 1,400 अंक गिरा

नई दिल्ली। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। संसेक्स और निफ्टी, दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान में खुले। बैंकिंग और प् सेक्टर के बड़े शेयरों में गिरावट की वजह से बाजार पर दबाव बना। निवेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ बयानों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। साथ ही, ळक् के आंकड़ों का भी इंतजार था। दोपहर बाद 12.50 बजे बीएसई संसेक्स 1,400 अंक 73,189 पर आ गया। छपजिल50 भी 22,150 अंक से नीचे पहुंच गया। इस गिरावट से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 9.61 लाख करोड़ रुपये घटकर 383.49 लाख करोड़ रुपये रह गया। लगातार पांचवें महीने शेयर मार्केट में गिरावट आई है। 1996 के बाद यह पहला मौका है जब लगातार पांच महीने शेयर मार्केट में गिरावट आई है।

सीजन के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी और बिजली चोरी को रोकने के लिए सघन अभियान चलाया जाए। मिलावटखोरों और बिजली चोरी करने वालों पर सख्त करवाई भी की जाए।

नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर हो कड़ी कार्रवाई

सीएम ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए सभी संबंधित विभागों को निरंतर अभियान चलाने के निर्देश दिए। कहा कि पुलिस राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियमित सघन चेकिंग करे। एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधियों की सूची बनाकर नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर कड़ी करवाई की जाए। उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिए कि राज्य में यातायात प्रबंधन की दिशा में विशेष प्रयास किए जाएं। पुलिस को रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए।

ताज के साए में सजी फोटो की दुनिया,फोटोग्राफर क्लब ऑफ आगरा ने लगाई फोटो की प्रदर्शनी

आगरा (संवाददाता)। आगरा में शुक्रवार को ताजमहल के पास स्थित मियां वाकी, ताज नेचर वॉक में ताज महोत्सव के अंतर्गत सामाजिक वानिकी विभाग के सहयोग से फोटोग्राफर क्लब ऑफ आगरा द्वारा फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। फोटोग्राफी में आगरा के 19 फोटोग्राफरों की फोटो प्रदर्शित की गईं। प्रदर्शनी में डीएम द्वारा खींची गई फोटो भी लगाई गई हैं। प्रदर्शनी का शुभारंभ फीता काट कर कमिश्नर शैलेंद्र कुमार ने किया। उनके साथ डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी, वन संरक्षक अनिल कुमार पटेल, डीएफओ आदर्श कुमार, डीएलएफ चंबल सेंचुरी चांदनी, फोटोग्राफर क्लब ऑफ आगरा के संस्थापक हर विजय सिंह वाहिया, वेदपाल धर उपस्थित रहे।

कमिश्नर शैलेंद्र कुमार ने कहा कि आगरा में वैश्विक स्तर के फोटोग्राफर हैं। इस बात की जानकारी शहर के लोगों को ही नहीं है। फोटोग्राफी कला है जिसे मेहनत, लगन और धैर्य से साधना होता है। वन संरक्षक अनिल कुमार पटेल ने कहा कि जंगल की खामोश दुनिया को तस्वीरों के माध्यम से फोटोग्राफर्स ने आवाज दी है। प्रदर्शनी में वाइल्ड लाइफ, प्रकृति, सनातन धर्म, होली आदि विभिन्न विषयों की झलक तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित की गई हैं। डीएफओ आदर्श कुमार ने बताया कि सामाजिक वानिकी विभाग द्वारा इस मौके पर चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। जिसमें ललित कला संस्थान, केंद्रीय विद्यालय, कर्नल ब्राइटलैंड स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इसके अलावा प्रदर्शनी में वन विभाग के दो रेंज ऑफिसर गजेंद्र पाल सिंह की फोटोग्राफी और दिशा सिंह की पेंटिंग की प्रदर्शित भी लगाई गई।

फोटोग्राफी प्रदर्शनी में हर विजय सिंह वाहिया द्वारा खींची गई तेंदुए और चीते की फोटो भी प्रदर्शित की गई। विश्व प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर ललित राजौरा की चीते की तस्वीरों ने भी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी, राम प्रताप सिंह, अनु सिंह, हरविजय सिंह वाहिया, ललित राजौरा, अर्पण भार्गव, रिकू शर्मा, गोपाल सिंह, डॉ अमोल शिरोमणि, पीयूष सचदेवा, हर्षदीप उप्पल, पीयूष सिंह चराग, पुरु शर्मा, कुलदीप चौधरी, मनोज तेनुगरिया, सिद्धार्थ जैन और वेदपाल धार द्वारा खींची गई तस्वीरें प्रदर्शनी में लगाई गईं।

मंदिर—मस्जिद में मानक से ज्यादा लगे लाउडस्पीकरों को उतरवाया गया

आगरा (संवाददाता)। किरावली में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए धार्मिक स्थलों से मानक से अधिक लगे लाउडस्पीकर हटवाए। एसीपी अछनेरा, एसडीएम किरावली और नायब तहसीलदार के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मंदिरों और मस्जिदों से अतिरिक्त लाउडस्पीकर उतारे गए। यह कदम क्षेत्र में शांति व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए उठाया गया। इसी अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की गई।

यूपी में 12,325 बसें संचालित हो रहीं, गांवों को जोड़ने के लिए 1540 मार्गों का निर्धारण : दयाशंकर सिंह

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि वर्तमान में परिवहन निगम द्वारा राज्य में 12,325 बसें संचालित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के असेवित (बस सेवा से पृथक) गांवों को (जोड़ने के लिए) सेवित किए जाने (बस सेवा से जोड़ने) के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 1540 मार्गों का नवीन निर्धारण किया गया है। विधानमंडल के बजट सत्र के सातवें दिन विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री सिंह सवालियों का जवाब दे रहे थे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक अखिलेश के प्रश्न के उत्तर में दया शंकर सिंह ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम स्वामित्व की 9,373 बसें एवं 2,952



निजी क्षेत्र की अनुबंधित बसों को मिलाकर कुल 12325 बसें राज्य में संचालित हैं। उन्होंने बताया कि ये बसें उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से ब्लॉक तहसील एवं जिलों को जोड़ते हुए बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान कर रही हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के

असेवित गांवों को सेवित किए जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 1540 मार्गों का नवीन निर्धारण किया गया है। इससे 28 हजार गांव जुड़ेंगे। इसके पहले समाजवादी पार्टी के ही सदस्य पंकज मलिक के प्रश्न के उत्तर में सिंह ने सदन को बताया कि प्रदेश में खराब

जर्जर रोडवेज बसों के स्थान पर नई बसें संचालित करने की योजना है और जो अयोग्य बसें हैं और नीलामी की अन्य शर्तें पूर्ण करती हैं तो उन्हें बस बेड़े से पृथक करके नीलाम किया जाता है। नीलाम की जाने वाली बसों के प्रतिस्थापन के लिए अंश पूंजी से वर्ष 2023-2024 और 2024-25 में विभिन्न श्रेणी की कुल 6138 बसें खरीदी गई हैं। मलिक ने पूरक प्रश्न के दौरान यह पूछा कि एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में कितनी बसें ऐसी हैं, जो 10 वर्ष से पुरानी हैं और पूरे प्रदेश में 15 वर्ष से पुरानी बसें हैं। इसके जवाब में सिंह ने कहा कि एनसीआर में कोई ऐसी बस नहीं है जो 10 साल से पुरानी हो और 11 लाख किलोमीटर से ज्यादा चली हो। 6138 नयी बसों की खरीद परिवहन के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी खरीद है।

इंदिरानगर के योगा पार्क के माली को दी गई विदाई

लखनऊ (संवाददाता)। इंदिरा नगर के ए-ब्लॉक स्थित योग पार्क में कार्यरत माली राम दुलारे के सेवानिवृत्त होने पर कॉलोनीवासियों ने एक भावभीनी विदाई पार्टी का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम लखनऊ के उद्यान अधीक्षक गंगा राम गौतम थे। इस अवसर पर सुपरवाइजर दया राम, इंदिरा नगर के सभी पार्कों के माली, विजेता द्विवेदी (फूड इंस्पेक्टर) एवं महेश वाल्मीकि (सफाई निरीक्षक) सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी लोगों ने राम दुलारे जी के समर्पण और उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। मुख्य अतिथि गंगा राम गौतम ने कहा कि जो ईमानदारी और निष्ठा पुराने कर्मचारियों में देखने को मिलती थी। वह अब नई पीढ़ी में कम नजर आती है। सभी उपस्थित लोगों ने राम दुलारे जी के सुखद, आनंदमय और स्वस्थ जीवन की कामना की। कार्यक्रम के संयोजक सुनील त्यागी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी कॉलोनीवासियों का आभार व्यक्त किया।

डीएम व एलडीए वीसी ने किया हेरिटेज जोन का निरीक्षण

लखनऊ (संवाददाता)। लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी और लखनऊ विकास प्राधिकरण वीसी प्रथमेश कुमार ने शुक्रवार सुबह हेरिटेज जोन का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें इमामबाड़ा और बेगम हजरत महल पार्क के पास कई जगह रास्तों को समझने में समस्या हुई। इसे लेकर कड ने इंजीनियरों को रास्तों पर साइनेज बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। अफसरों ने सबसे पहले कैसरबाग हेरिटेज जोन पहुंचे। यहां उन्होंने एक रंग में रंगी जा रही इमारतें देखी। इंजीनियरों ने उन्हें चौराहे का इतिहास बताते हुए पूरी प्लानिंग बताई। इस दौरान सड़क फेंले केबल को हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही चौराहों पर साफ-सफाई की व्यवस्था बनाए रखने के लिए डस्टबीन रखने का आदेश दिया। जिलाधिकारी विशाख जी ने बड़ा इमामबाड़ा का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार से ने हेरिटेज जोन में हो रहे कामों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने इंजीनियरों को समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए।

भी खरीदारी करने लोग आ रहे हैं। चावल, साबूदाना इमरती को भी लोग पसंद कर रहे हैं। पापड़ का मूल्य 150 से लेकर 320 रुपये तक है। बढ़ते मोटे अनाज के चलन के साथ चिप्स और पापड़ की तमाम वैरायटी बाजार में आ गई है। इन रेडीमेड आइटम को बाजार से लाइए। घी या तेल में तलिये और रख दीजिए मेहमानों की प्लेट में। मक्का के चिप्स हों या मोटे अनाज के छोटे पापड़ या फिर आलू के लच्छे। मोटे अनाज वाले यह रेडीमेड चिप्स और कचरी भी लोगों की पसंदीदा है। मोटे अनाज वाले इन आइटम की रेंज 80 से लेकर 175 रुपये प्रति किलो तक हैं। इनमें कचरी, पापड़, आरारोट आधारित रंगीन भगवा चिप्स, लच्छा समेत विभिन्न आइटम हैं।

ओमप्रकाश राजभर के बेटे को मिली जान से मारने की धमकी, शरम्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया शेयर



लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को जान से मारने की धमकी मिली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर धमकी दी गई है। विवेक पासी नाम से इंस्टाग्राम पर मौजूद सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें शरम्स सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अरविंद राजभर की हत्या करने की धमकी देता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, उसने अरविंद राजभर के लिए अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल

किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सुभासपा के प्रदेश कार्यालय प्रभारी धर्मप्रकाश चौधरी ने शरम्स के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। हजरतगंज कोतवाली में बीएनएस की धारा 315(4) और आईटी एक्ट 66डी के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर के मुताबिक, आरोपी ने पड्यंत्र कर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं पूर्व राज्यमंत्री डॉ. अरविंद राजभर की फोटो को मनमाने तरीके से एडिट व छेड़छाड़ कर उन्हें गंदी-गंदी गाली व जान से मारने की धमकी दी। साथ

ही उनके फोटो का भद्दा वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया साइट पर अपलोड किया और उसने इस तरह से उनके (अरविंद राजभर) फोटो का कई फर्जी व मनगढ़ंत वीडियो बनाकर उन्हें भद्दी-भद्दी व घोर आपत्तिजनक और जातिगत गालियां दी। इसके बाद वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया है, जिसके कारण पार्टी की छवि को समाज व प्रदेश में धूमिल और बदनाम किया गया है। इसमें आगे कहा गया कि उसने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो डालकर अरविंद राजभर की हत्या करने की धमकी भी दी है, जिसके वायरल होने से लोगों में

भय व्याप्त हो गया है। उपरोक्त आईडी धारक द्वारा किया गया उक्त कृत्य व धमकी एक गंभीर व आपत्तिजनक आपराधिक कृत्य है, जिससे दोषी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करना अत्यंत आवश्यक है। फिलहाल हजरतगंज थाने के एडिशनल एसएचओ सुधाकर सिंह ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बांधों की सुरक्षा पर विश्वबैंक कार्यशाला का आयोजन

लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में रायबरेली रोड स्थित वाल्मी भवन के विश्वेश्वरैया सभागार में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। विश्व बैंक पोषित राज्य बांध सुरक्षा संगठन और स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट ने इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ हुआ। मुख्य अभियंता ज्ञानेंद्र शरण और तकनीकी सलाहकार रमेश चंद्रा ने दीप प्रज्वलित किया। मुख्य अभियंता ज्ञानेंद्र शरण ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक हितों को प्राथमिकता देते हुए पुराने अनुभवों के साथ नई तकनीक का उपयोग करना आवश्यक है। तकनीकी सलाहकार रमेश चंद्रा ने बताया कि परियोजना के दूसरे चरण में 30 और तीसरे चरण में 9 बांधों को शामिल किया गया है। बांध सुरक्षा अधिनियम-2021 के तहत इन बांधों की सुरक्षा, समस्याओं और रखरखाव पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यशाला के प्रबंधक सहायक अभियंता सुनील कुमार मिश्र और पंकज कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए बांधों की सुरक्षा और विकास कार्यों को गति देना था। कार्यक्रम में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के 40 से अधिक अधीक्षण, अधिशाषी और सहायक अभियंता उपस्थित रहे। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई अभियंताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

हिन्दी का पठन पाठन बंद कर राष्ट्रीय एकता, अखण्डता को कमजोर कर रही है तमिलनाडु सरकार-रालोद सपा और कांग्रेस स्पष्ट करे अपना मत—दुबे

लखनऊ (संवाददाता)। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने इण्डी गठबंधन के प्रमुख दल डीएमके द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के विरोध पर इण्डी गठबंधन के प्रमुख घटक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से अपना मत स्पष्ट करने को कहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा है कि तमिलनाडु में डीएमके द्वारा त्रिभाषा फार्मूले का विरोध कर धिनौनी राजनीति की जा रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उनकी सरकार तमिलनाडु में हिन्दी थोपने का झूठा आरोप लगा रही है। उनका कहना कि वह बहुभाषी होने के पक्षधर है लेकिन राज्य में हिन्दी का अनिवार्य स्वीकार्य नहीं है। श्री दुबे ने कहा कि 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के समय त्रिभाषा फार्मूला बना जिसका राज्यों में हिन्दी अंग्रेजी

सहित एक क्षेत्रीय भाषा पढाये जाना तय हुआ, उस समय भी तमिलनाडू में इस फार्मूले को लागू नहीं किया गया सिर्फ तमिल और अंग्रेजी ही लागू हुयी। 1986 में भी इस फार्मूले को अपनाया गया किन्तु तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया। तमिलनाडु सरकार इस फार्मूले का विरोध कर राष्ट्रीय एकता का विरोध कर रही है। 2020 में नई शिक्षा नीति बनाई गई जिसको लागू करते हुये यह कहा गया कि हिन्दी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा का फार्मूला अपने राज्य में लागू करे और कोई भाषा जबरन थोपी नहीं जायेगी। केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित करने का काम इसलिए कर रही है ताकि राष्ट्रीय एकता को और सशक्त और मजबूत बनाया जा सके

लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार इसका विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि भाषा को लेकर संकीर्ण सोच से ऊपर उठने की बजाय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री राजनीतिक स्वार्थ के कारण इस फार्मूले का विरोध कर रहे है और विरोध करना इनका पुराना इतिहास है। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान 1918 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की थी। तमिलनाडु सरकार हिन्दी के पठन पाठन को बंद करके राष्ट्रीय एकता, अखण्डता को कमजोर कर रही है क्योंकि उसे यह लगता है कि त्रिभाषा फार्मूला लागू होने से राजनीति का रंग रोगन बदलेगा और शिक्षा का स्तर भी आगे न बढ़ पाये इसलिए उसका विरोध कर रही है और इसी तरह नई शिक्षा नीति हिन्दी, अंग्रेजी

सहित क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को बचाने की दिशा में काम कर रही है लेकिन देश की जनता यह जानना चाहती है कि इण्डी गठबंधन के प्रमुख घटक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इस पर क्यों चुप्पी साधे हुए है और हिन्दी के विरोध पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उनकी यह चुप्पी हिन्दी के सम्मान के साथ अन्याय है और उससे यह स्पष्ट है सपा और कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिन्दी भाषा को लगातार अपमानित होते देख रही है। राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश की जनता से हिन्दी के मुद्दे पर प्रदेश की जनता से भाषा, संस्कृति और सम्मान के लिए सहयोग की अपील करता है और इस मुद्दे पर प्रदेश की जनता की बीच सपा और कांग्रेस करने के लिए अभियान भी चलायेगा।

गड़बड़ी पर लाइनमैन से लेकर चेयरमैन तक होगी कार्रवाई : शर्मा ऊर्जा मंत्री ने विधान सभा में विपक्ष को दिया जवाब

लखनऊ (संवाददाता)। विधानसभा में आज बिजली आपूर्ति का मामला उठा। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने नियम-56 के तहत मामला उठाते हुए ऊर्जा मंत्री से जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शुक्रवार को विधान सभा के बजट सत्र में नियम 56 के तहत विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष कहता है कि उत्तर प्रदेश में नागालैण्ड से भी कम बिजली आपूर्ति की जा रही, जबकि प्रदेश में देश की सर्वाधिक 30,618 मेगावॉट विद्युत की आपूर्ति की गई है और इस मामले में महाराष्ट्र से भी हमारा प्रदेश आगे निकल गया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश को 12-14 हजार मेगावॉट विद्युत आपूर्ति की जाती थी, उसका ढाई गुना अधिक बिजली की आपूर्ति इस वर्ष प्रदेश को की गई। प्रयागराज में डिजिटल महाकुम्भ के सफल आयोजन एवं बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की क्रांति से विपक्षी आश्चर्यचकित हैं। ऊर्जा मंत्री ने विपक्ष द्वारा बिलिंग एजेंसियों एवं विद्युत



कार्मिकों की मनमानी के सवाल पर कहा कि जहां कहीं से भी विद्युत कार्मिकों के खिलाफ गड़बड़ी करने एवं उपभोक्ताओं का उत्पीड़न संबंधी शिकायतें आती हैं। ऐसे कार्मिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि विद्युत व्यवस्था के सुधार में गड़बड़ी पाये जाने पर लाइनमैन से लेकर संबंधित डिस्कॉम के एमडी एवं यूपीपीसीएल के एमडी व चेयरमैन तक को भी बख्शा नहीं जायेगा। बिजली बिलों में गड़बड़ी की

शिकायत पर 3394 संविदा कार्मिकों एवं 85 कार्मिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई तथा 28 कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गई है। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि भ्रष्टाचार में लिप्त एवं गड़बड़ी करने वाले विद्युत कार्मिकों को बख्शा नहीं जायेगा, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में आरडीएसएस योजना के तहत 16

हजार करोड़ रुपये तथा बिजनेस प्लान के तहत 03 वित्तीय वर्ष में 5-5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य कराये गये। इसमें जर्जर तारों, विद्युत पोल तथा बांस-बल्ली में संचालित लाइन हटाकर व्यवस्थित किया। क्षतिग्रस्त एवं ओवरलोड ट्रांसफार्मर व फीडर की क्षमता वृद्धि की गई। सपा सरकार ने डेढ़ लाख मजदूरों का विद्युतीकरण नहीं किया गया था, जिसमें से 1.21 लाख मजदूरों का विद्युतीकरण कराया गया। शेष 20 हजार से अधिक मजदूरों के विद्युतीकरण की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश के 3.55 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं में से मात्र 1 प्रतिशत के बिलों में गड़बड़ी आ रही है। जिसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को बिजली कनेक्शन लेने में कोई समस्या नहीं आ रही है। आजादी के बाद से सर्वाधिक विद्युत कनेक्शन किसानों को दिये गये हैं। साथ ही किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिलों को भी माफ करने का कार्य प्रदेश की योगी सरकार ने ही किया है।

कृषि विभाग में कर्मचारियों का 13 सूत्री मांगों को लेकर धरना

लखनऊ (संवाददाता)। कृषि विभाग लिपिक संवर्ग की लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर शुक्रवार को विभागीय कर्मियों ने निदेशालय में एक दिवसीय धरना दिया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। लिपिक संगठन के अध्यक्ष धर्मेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेशभर में 18 फरवरी को भोजनावकाश के दौरान विरोध दिवस मांग दिवस मनाते हुए प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया गया था। लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी क्रम में आज निदेशालय में प्रदर्शन कर अपनी 13 प्रमुख मांगों को रखा गया। लिपिक संवर्ग के पुनर्गठन के लिए शासन को अपेक्षित प्रस्ताव भेजा जाए ताकि बढ़ते कार्यों के अनुसार पदों का पुनर्विभाजन और उच्चीकरण हो सके। पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी हो, जिससे कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक और वरिष्ठ

सहायक से प्रधान सहायक की पदोन्नति हो सके। मृतक आश्रितों की पदोन्नति की कार्रवाई 2022 से लंबित है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाए। मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए, जिससे उनके परिवार को राहत मिल सके। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा जल्द भरा जाए। अद्यतन वरिष्ठता सूची जारी की जाए। कार्यालय भवनों की मरम्मत कराई जाए ताकि कर्मचारियों को सुरक्षित कार्यस्थल मिल सके। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए बजट और संसाधन मुहैया कराए जाएं। ऑफिस, मानव संपदा पोर्टल पर कार्य हेतु मंडलवार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। नवसृजित जनपदों (हापुड़, कासगंज, शामली, सम्भल, अलीगढ़ मंडल) में नए पद सृजित किए जाएं। कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति के बावजूद लिपिकों से कार्य कराना बंद किया जाए और

जिम्मेदारी ऑपरेटरों को दी जाए। पुराने आवासों की मरम्मत तथा नए आवासों का निर्माण कराया जाए। कार्यालयों में चौकीदारों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया

गया तो लिपिक संवर्ग को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। इस मौके पर फेडरेशन के अध्यक्ष दिवाकर सिंह और महामंत्री विनोद कनौजिया ने भी मौजूद रहे।

लगातार 13वीं बार सतीश पाण्डेय अध्यक्ष पद पर विजयी

लखनऊ (संवाददाता)। लखनऊ के जवाहर भवन-इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ के चुनाव परिणाम 14 घंटे चली मतगणना के बाद घोषित कर दिए गए। चुनाव अधिकारी डीके मिश्रा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में सतीश कुमार पाण्डेय ने 2025 मत प्राप्त कर 1321 मतों के अंतर से पवन कुमार गौतम (704 मत) को पराजित किया। मंत्री पद पर आशीष प्रकाश श्रीवास्तव 887 मतआकिल सईद बब्बू 984 म चुनाव अधिकारी ने बताया कि कुल 2901 मतदाताओं में से 2777 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, [यह 95.7: मतदान के साथ अब तक का रिकॉर्ड मतदान है। चुनाव के सफल संचालन के लिए चुनाव समिति को धन्यवाद दिया गया। विजयी प्रत्याशियों ने कर्मचारी हितों के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करने का संकल्प लिया।

सिपाही की बदसलूकी से नाराज वकीलों का आलमबाग थाने के बाहर हंगामा

लखनऊ (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में आलमबाग कोतवाली के बाहर वकील जमकर हंगामा कर रहे हैं। सभी थाने के बाहर सड़क पर बैठे हैं। जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। इनका आरोप है कि एक सिपाही द्वारा बदसलूकी की गई है। सभी वकील इसी बात से नाराज हैं। वकीलों ने चेतावनी दी है कि यदि दोषी सिपाही को लाइन हाजिर नहीं किया गया, तो आगे की कार्रवाई का निर्णय लेंगे। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही एसीपी कैंट मौके पर पहुंचे। वे वकीलों से बातचीत कर शांत करने का प्रयास कर रहे हैं।

अंसल सिटी का बिजली कनेक्शन कटा,4.78 करोड़ रुपए बिल बकाया

लखनऊ (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में अंसल सुशांत गोल्फ सिटी ने 4.78 करोड़ रुपए का बकाया बिजली बिल नहीं जमा किया तो विभाग ने टाउनशिप का कनेक्शन काट दिया है। कनेक्शन काटने से पांच हजार लोग बिजली की समस्या से जूझेंगे। अफसरों ने टाउनशिप प्रबंधन को शुक्रवार 10 बजे तक बिल जमा करने का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन, प्रबंधन ने बिल जमा नहीं किया। राजभवन खंड के अधिशासी अभियंता अनुज कुमार ने टाउनशिप प्रबंधन को जारी नोटिस में कहा है कि जनवरी और फरवरी का मिला कर कुल 6.78 करोड़ रुपए का बिल बना है। जिसमें से बार बार नोटिस भेजने के बाद सिर्फ दो करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। उन्होंने बताया कि बाकी के 4.78 का भुगतान नहीं किया गया। वही विभाग की नोटिस के बाद टाउनशिप में रहने वाले करीब 5000 परिवारों एवं मॉल के कारोबारियों अंधेरे में चले गए हैं।

एक्सयूवी स्टार्ट करते ही इंजन में लगी आग,दमकल ने बुझाया

लखनऊ (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार तड़के एक एक्सयूवी में इंजन में शार्ट सर्किट के बाद आग लग गई। बोनट से धुंआ निकलते कार मालिक ने सरोजनी नगर फायर स्टेशन को सूचना दी। दमकल एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग से कार पूरी तरह से चल गई। घटना के वक्त कार मालिक प्रयागराज अपनी ड्यूटी पर जाने को निकल रहे थे। तभी आग लग गई।

ऑनलाइन फर्नीचर बेचने के नाम पर ठगी, पीजीआई थाने में केस दर्ज

लखनऊ (संवाददाता)। लखनऊ के तेलीबाग स्थित गांधी नगर में एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित बख्तियार अहमद सिद्दीकी ने पीजीआई थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना 27 फरवरी की है। पीड़ित को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉलर ने खुद को सीआरपीएफ का अधिकारी बताया। उसने कहा कि उसका लखनऊ से ट्रांसफर हो गया है। इसलिए वह अपना घरेलू सामान बेचना चाहता है। आरोपी ने फर्नीचर, अलमारी और टीवी समेत कई सामान की कीमत 95 हजार रुपए बताई। उसने वॉट्सऐप पर सामान की फोटो भेजी।

जावेद अख्तर से माफी मांग कंगना ने खत्म की 5 साल की कानूनी लड़ाई, कोर्ट के सामने हुई सुलह



मुंबई (एजेंसी)। एक्ट्रेस कंगना रनौत और गीतकार जावेद अख्तर के बीच कई सालों से कानूनी लड़ाई चल रही है। जावेद अख्तर के मानहानि मामले में कई बार कंगना को समन जारी हो चुका है, लेकिन वह कभी भी तारीख पर नहीं पहुंची। वहीं, अब 5 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, दोनों ने आपसी सहमति से मुकदमा खत्म करने का फैसला किया है। कंगना ने जावेद अख्तर से माफी मांग ली है और उनके साथ सुलह कर ली है। कंगना रनौत ने लिखित रूप में कहा कि वह जावेद अख्तर का बहुत सम्मान करती हैं और

उनके बयानों की वजह से उन्हें जो असुविधा हुई, उसके लिए वह माफी मांगती हैं। कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच चल रहे इस कानूनी विवाद की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी, जब जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कंगना ने इसके बाद काउंटर याचिका दायर की थी। इस मामले में पिछले 40 सुनवाईयों के दौरान, कंगना कोर्ट में कभी नहीं आई, जबकि जावेद अख्तर नियमित रूप से कोर्ट में पेश होते रहे। इसी सप्ताह मंगलवार को हुई सुनवाई के

दौरान, कंगना फिर से कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके बाद गीतकार के वकील ने एक्ट्रेस के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की अपील की थी। आखिरकार आज कंगना रनौत कोर्ट में पेश हुई, जहां जावेद अख्तर भी कोर्ट में मौजूद थे। इस दौरान कंगना ने जावेद अख्तर के साथ सुलह के सभी शर्तों को स्वीकार किया। दोनों पक्षों की सहमति से यह मामला समाप्त हुआ और कंगना ने चार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बयान दिया, जिन्हें उन्होंने सुलह के दौरान स्वीकार किया। सुलह के बाद, कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच अच्छे माहौल में बातचीत हुई और दोनों ने भविष्य में एक साथ काम करने पर भी चर्चा की। कंगना ने सोशल मीडिया पर इस सुलह को लेकर एक पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा, आज जावेद जी और मैंने अपने कानूनी केस को मध्यस्थता के माध्यम से खत्म कर दिया है। मध्यस्थता के दौरान जावेद जी बहुत दयालु रहे। उन्होंने मेरी अगली निर्देशित फिल्म के लिए गाना लिखने पर भी सहमति जताई है। इसके साथ, कंगना ने जावेद अख्तर के साथ एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें वह उनके बगल में हंसते हुए पोज दे रही हैं।

समृद्ध भारत के निर्माण में राजेंद्र प्रसाद का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा : योगी



लखनऊ (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले राष्ट्रपति 'भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि समृद्ध भारत के निर्माण में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, "महान स्वाधीनता सेनानी, देश के प्रथम राष्ट्रपति,

संविधान सभा के अध्यक्ष, 'भारत रत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि! योगी ने कहा "मूल्यों और आदर्शों से सुवासित आपका संपूर्ण जीवन लोकतंत्र की पाठशाला है। 'समृद्ध भारत के निर्माण में आपके योगदान सदैव स्मरणीय रहेंगे। राजेंद्र प्रसाद का जन्म तीन दिसंबर 1884 को बिहार प्रांत में हुआ था और 28 फरवरी 1963 को 78 वर्ष की उम्र में उनका पटना में निधन हो गया।

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे 1 मार्च को जाएंगे उदयपुर

उदयपुर (एजेंसी)। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागडे एक मार्च को उदयपुर प्रवास पर रहेंगे। जिला कलक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को कहा कि बागडे शनिवार को शाम 4.15 बजे विमान से डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डा पहुंचेंगे। वहां से सड़क मार्ग द्वारा उदयपुर शहर पहुंच कर आरएनटी मेडिकल कॉलेज परिसर में नेशनल मेडिकॉल आर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित अखिल भारतीय वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। बागडे शाम 6.45 बजे पुनः डबोक पहुंच कर विमान से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 34 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, बजट सत्र के दौरान राज्यपाल ने अभिभाषण में किया ऐलान

पटना (एजेंसी)। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य सरकार के रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए आज कहा कि इस वर्ष विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले प्रदेश के 34 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शुक्रवार को बजट सत्र के पहले दिन बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि शुरु से ही सरकार का प्रयास है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार के अवसर मिलें। वर्ष 2020 से सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देने का निश्चय किया गया। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अब तक नौ लाख 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। शेष पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। राज्यपाल ने कहा कि अब राज्य सरकार ने तय किया है कि इस वर्ष चुनावों की घोषणा के पहले ही युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जायेगी। जहां तक रोजगार की बात है अबतक 10 लाख की जगह 24 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है तथा चुनावों की घोषणा के पहले ही 34 लाख लोगों को रोजगार मिल जायेगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरु से ही शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बड़ी संख्या में नये स्कूल खोले गये हैं। विद्यालयों में एक ओर जहां पोशाक, सार्इकल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएं लागू की गई वहीं दूसरी ओर नये विद्यालय भवन, क्लासरूम, शौचालय एवं चहारिदिवारी बनाकर विद्यालयों की आधारभूत संरचना को मजबूत किया गया है। राज्यपाल ने



कहा कि बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी का परिणाम है कि

इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक हो गयी है।

दिल्ली विधानसभा में विपक्षी विधायकों के साथ अन्याय, आतिशी ने लिखा विजेन्द्र गुप्ता को पत्र

नयी दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली विधानसभा में विपक्षी विधायकों के खिलाफ हुए अत्याचार पर नेता विपक्ष आतिशी ने चिंता जताई है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने विधानसभा में हाल ही में हुए घटनाक्रम की कड़ी आलोचना की है।

आतिशी ने पत्र में बताया कि मंगलवार, 25 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने मोदी-मोदी के नारे लगाए, जबकि विपक्ष के विधायकों ने बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों का सम्मान करते हुए जय भीम के नारे लगाए। आतिशी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि विपक्ष के 21 विधायकों को केवल



जय भीम के नारे लगाने के कारण तीन दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद, जब निलंबित विधायक लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने गए, तो उन्हें विधानसभा के गेट से 200 मीटर पहले ही रोक लिया गया और परिसर में दाखिल होने से मना कर दिया गया। आतिशी ने इसे लोकतांत्रिक

अधिकारों का उल्लंघन और जनता द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान बताया। पत्र में आतिशी ने यह भी कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, जब वह विपक्ष के नेता थे,

तो उन्हें सदन से निलंबित किए जाने पर भी गांधी प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन करने से नहीं रोका जाता था। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या यह संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन नहीं है? आतिशी ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि संसद में जब किसी सांसद को निलंबित किया जाता है, तो उन्हें संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के

समक्ष प्रदर्शन करने की अनुमति होती है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में यह पहली बार हुआ है कि निलंबित विधायकों को परिसर में घुसने तक नहीं दिया गया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जिस नियम का हवाला देकर विपक्षी विधायकों को रोका गया, उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि निलंबित विधायक विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते या गांधी और अंबेडकर की प्रतिमा तक नहीं जा सकते। आतिशी ने अंत में कहा कि अगर विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा और विधायकों को अपने सवाल उठाने से रोका जाएगा, तो लोकतंत्र कैसे बच पाएगा? उन्होंने अध्यक्ष से आग्रह किया कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी विधायक को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित न किया जाए।

बिखरी जुल्फें और कजरारी आंखें..मॉम-टू-बी कियारा आडवाणी का स्टनिंग फोटोशूट, ब्लैक ड्रेस और गोल्डन जूलरी में दिखा क्लासी लुक

एक्ट्रेस कियारा आडवाणी इस वक्त काफी सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने पति व एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा संग फैंस को मां बनने की गुड न्यूज दी, जिसके बाद उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। वहीं, इस गुड न्यूज की घोषणा से पहले मॉम-टू-बी कियारा ने गुरुवार रात मुंबई में एक इवेंट अटेंड किया, जहां वह अपने ग्लैमरस लुक का जलवा बिखरेती नजर आई। इस लुक की तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की हैं, जिन्हें फैंस खूब लाइक कर रहे हैं। लुक की बात करें तो इस दौरान कियारा आडवाणी बेलेंसियागा का ब्लैक आउटफिट पहने बेहद स्टनिंग दिखीं। गोल्डन जूलरी के साथ अपनी ड्रेस को कियारा ने क्लासी टच दिया।

वह गले में गोल्डन पेंडेंट और कानों में ईयररिंग्स पहने नजर आईं। कजरारी आंखें, न्यूड लिपस्टिक और खुले बालों के साथ कियारा ने अपना लुक कंप्लीट किया और साथ ही हाई हील्स पेयर कीं। अपने इस लुक से फैंस को इम्प्रेस करते हुए कियारा कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक पोज देती नजर आईं।

कई तस्वीरों में वह खुद का मेकअप भी करती दिखीं। बता दें कि कियारा आडवाणी ने 7 फरवरी 2023 को सिद्धार्थ मल्होत्रा संग राजस्थान के जैसलमेर में शादी रचाई थी। परिवार के सदस्य और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में दोनों की वेडिंग धूमधाम से हुई थी। वहीं, अब शादी के 2 साल बाद ये कपल मम्मी-पापा बनने जा रहा है।



तीस्ता नदी परियोजना पर बांग्लादेश ने भारत के विरुद्ध चीन से मदद मांगी

आशीष विश्वास

यह कोई रहस्य नहीं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अंतरिम बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार डॉ. मोहम्मद यूनस के बीच कोई खास रिश्ता नहीं है। कुछ हद तक विरोध आभासी रूप से, दोनों में एक असामान्य विशेषता है—यदि आवश्यक हो तो मौजूदा राजनयिक मानदंडों और परंपराओं को रौंदने का उनका दृढ़ संकल्प, क्योंकि वे कम से कम समय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिया है कि दक्षिण एशिया से संबंधित मामलों में, वह बांग्लादेशी संवेदनाओं के बारे में किसी भी स्पष्ट चिंता के बिना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अधिक निकटता से जुड़ना पसंद करते हैं। ट्रंप के नेतृत्व वाली सरकार से निपटने में आने वाली कठिनाइयों से अनभिज्ञ, चालाक डॉ. यूनस अपने तरीके से पलटवार कर रहे हैं। 1971 के बाद के पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को फिर से जगाने के बाद, बांग्लादेश ने अब चीन को पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक तरीके से लुभाना शुरू कर दिया है, लेकिन इस दिशा में उसके प्रयास, जैसा कि पहले पाकिस्तान के साथ हुआ था, निकट भविष्य में महत्वपूर्ण लाभ नहीं ला पाये हैं। यह देखना मुश्किल नहीं है कि ऐसा क्यों है। डेमोक्रेट्स से पहले के समर्थन से कटे हुए, यूनस के नेतृत्व वाला बांग्लादेश, अमेरिका के वर्तमान पसंदीदा भारत के लिए घर के नजदीक जितना संभव हो सके उतना मुश्किल बनाकर ट्रंप प्रतिष्ठान को धोखा देना चाहेगा। ढाका के इस कदम से कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश ने अभी तक दक्षिण एशिया में एक संप्रभु तथा स्वतंत्र देश के रूप में काम करने में बहुत प्रगति नहीं की है, क्योंकि उसे अपने बड़े पड़ोसियों जैसे चीन या भारत से स्पष्ट समर्थन की आवश्यकता रहती है। बांग्लादेश के लिए संकट यह है कि यूनस की अन्य योग्यताएं चाहे जो भी



हों, मूल रूप से एक अनिर्वाचित पदाधिकारी हैं, जो राजनीतिक प्रतिष्ठा का आनंद ले रहे हैं परन्तु अत्यधिक जटिल दक्षिण एशियाई राजनीतिक खदानों से गुजरते हुए कूटनीतिक रूप से अभद्र साबित हो रहे हैं। उनकी दुर्दशा पर विचार करें। इस व्यक्ति को एक हिंसक तख्तापलट के माध्यम से सत्ता में लाया गया है, जिसकी वजह से 5 अगस्त 2024 से बांग्लादेश में 2000 लोगों की जानें जा चुकी हैं (और यह संख्या अभी भी बढ़ रही है!)। उनके मुख्य घरेलू समर्थकों में, कट्टरपंथी जमातीध्वंसात्मक चरमपंथी सुर में सुर मिलाते हैं, यहां तक कि शक्तिशाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को भी दरकिनार कर देते हैं, जो चुनावों के माध्यम से वैध रूप से अर्जित राजनीतिक सत्ता का प्रमुख दावेदार है। ढाका से भारत के खिलाफ शुरुआती धमकियां, जिनमें पाकिस्तान या चीन से उधार लिये गये परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके या संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारे को काट कर परमाणु हमला करने की कुछ विचित्र (और हास्यास्पद!) कल्पनाएं शामिल थीं, जो इस्लामी चरमपंथियों के दबाव में की गयी थीं। गौरतलब है कि बीएनपी ने शुरू में यूनस का समर्थन करने के बावजूद कभी भी खुद को इस तरह की मूर्खतापूर्ण कॉल और चेतावनियों से नहीं जोड़ा। बहुत देर

से, महान मुख्य सलाहकार को एहसास हुआ कि उन्हें गलत सलाह दी जा रही थी, अगर वास्तव में स्वदेशी कट्टरपंथी इस्लामी उग्रवादियों की भीड़ द्वारा उन्हें गुमराह नहीं किया जा रहा था तो। इन लोगों ने पाकिस्तान, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, मध्य पूर्व और अन्य देशों से सब्जियां, चावल और चीनी आयात करने की कोशिश की, और भारत का पूरी तरह से बहिष्कार किया! सौभाग्य से, अंतरिम सरकार ने आखिरी समय में अपना रुख बदल दिया और भारत विरोधी बयानबाजी को कम किया और गुस्साए प्रदर्शनकारियों के बढ़ते दबाव के तहत सीमा व्यापार और भारत से आवश्यक वस्तुओं के आयात को पहले की तरह सामान्य करने की कोशिश की! ऐसा नहीं है कि यूनस की टीम के पास ज्यादा विकल्प थे। बीएनपी ने पहले ही मुख्य सलाहकार के प्रति अपनी बढ़ती हुई अधिरता के पर्याप्त संकेत दे दिये हैं, जो पिछले छह महीनों के दौरान अपने सभी कदमों के माध्यम से किसी न किसी बहाने से लंबे समय से प्रतीक्षित चुनावों को रोक रहे हैं। देश की दूसरी प्रमुख ताकत, अवामी लीग (एएल), जिसकी नेता श्रीमती हसीना वाजेद अभी भी निर्वासन से काम कर रही हैं, पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन बीएनपी ने भी इसका विरोध किया है। बांग्लादेश में

वैध लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होने के नाते, अनुभवी बीएनपी नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि एएल के बिना आम चुनाव आयोजित करना, जैसा कि जमात सुनिश्चित करना चाहते हैं, उन्हें घर या विदेश में शायद ही कोई विश्वसनीयता हासिल होगी। इसके अलावा जमात के नेताओं ने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति के लिए मुख्य सलाहकार की आलोचना करना शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हसीना के प्रशासन के तहत उनके देश को परेशान करने वाली सभी बुराइयां—शीर्ष पर भ्रष्टाचार, राज्य प्रायोजित हिंसा और अराजकता, असहमति का बलपूर्वक दमन, लोगों के बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाली उच्च मुद्रास्फीति, सांप्रदायिक हमलों का लगातार प्रकोप—बेरोकटोक जारी है। एकमात्र उपाय है कि एक बार फिर से आम चुनाव करवाये जायें। अंतरिम सरकार ने अभी तक अपने मुख्य प्रायोजक की ओर से इस आभासी अभियोग का जवाब नहीं दिया है। यह हताशा की हद है कि ढाका ने तीस्ता जल बंटवारे के मुद्दे पर एक सावधानीपूर्वक नियंत्रित भारत विरोधी आंदोलन को प्रायोजित करने की कोशिश की है। यह कदम टीम यूनस को बहुत जरूरी समय देगा और वर्तमान शासकों और उनके सलाहकारों के खिलाफ बढ़ते जनक्रोध को अस्थायी रूप से कम करेगा। तीस्ता नदी को बचाने के तरीके के बारे में चीन के साथ बातचीत फिर से शुरू हो गयी है। ढाका स्थित राजनयिकों के बीच वार्ता में इस परियोजना को पुनर्जीवित किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, चीन द्वारा अंतरिम शासकों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने की संभावना, कम से कम पहले के अमेरिकी समर्थन के नुकसान की भरपाई के लिए, चर्चाओं में भी शामिल थी। चीन के साथ गुप्त कूटनीतिक पहल के परिणामस्वरूप अब तक चीन की ओर से एक विशिष्ट प्रोटोकॉल—अनुमोदित

प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजिंग हलकों ने बताया कि नदी विशेषज्ञों ने दो साल के लंबे अध्ययन और सर्वेक्षण के बाद तीस्ता नदी को पुनर्जीवित करने की प्रस्तावित बांग्लादेश योजना के जवाब में पहले ही अपने सुझाव दे दिये हैं। यह बांग्लादेश को बताना था कि क्या वह इस परियोजना पर आगे बढ़ना चाहता है, जिसके लिए चीन आवश्यक होने पर धन देने के लिए तैयार है। इसके अलावा, पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर दोनों देश आधिकारिक समझौते के बाद ढाका द्वारा अपने बड़े उत्तरी पड़ोसी से पहले की तरह अधिक हथियार और गोला-बारूद खरीदने पर भी चर्चा शुरू कर सकते हैं। हालांकि, बांग्लादेश की मदद करने के लिए विशिष्ट स्थितियों में चीन द्वारा हस्तक्षेप करने की संभावना के बारे में, बीजिंग की प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल—परफेक्ट थी, जैसा कि प्रमुख शक्तियों के साथ आम तौर पर होता है। ढाका को बताया गया कि बड़ा देश अपने छोटे क्षेत्रीय पड़ोसियों को व्यापार और व्यवसाय के विकास सहित सभी द्विपक्षीय मामलों में मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन बीजिंग सभी देशों के साथ समान संप्रभु साझेदार के रूप में व्यवहार करने में विश्वास करता है, इसलिए चीनियों को भरोसा था कि परिपक्व घरेलू राजनीतिक प्रतिष्ठान और साथ ही बांग्लादेश के लोकतंत्र—प्रेमी लोग, घर और विदेश दोनों में अपनी समस्याओं से निपटने और उन्हें सुलझाने में पूरी तरह सक्षम हैं। अगर बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के लहजे पर गौर करें, तो चीन के ऐसे अच्छे, सुकून देने वाले शब्दों की आधिकारिक तौर पर सराहना की गयी। हालांकि, अंतरिम सरकार के लिए ये शब्द बहुत कम राहत लेकर आये, जो अभी भी नयी ट्रम्प टीम की कड़ी आलोचना से परेशान है।



समीर अरोड़ा (ब्यरो चीफ दिल्ली)

रेड रोज न्यूज़ की तरफ से
देशवासियों को होली की
हार्दिक शुभकामनाएं



वेद पाल पंचल (रिपोर्टर)

रेड रोज न्यूज़ की तरफ से
देशवासियों को होली की
हार्दिक शुभकामनाएं



जफर खान (रिपोर्टर मैनपुरी 30प्र0)

रेड रोज न्यूज़ की तरफ से
देशवासियों को होली की
हार्दिक शुभकामनाएं



गे सुल हसन (रिपोर्टर दिल्ली)

रेड रोज न्यूज़ की तरफ से
देशवासियों को होली की
हार्दिक शुभकामनाएं

RED ROSE NEWS

WE ARE HIRING

रेड रोज न्यूज़ को भारत में समाचार हेतु
न्यूज़ रिपोर्टर, कंटेंट राइटर, न्यूज़ एंकर,
वॉइस एंकर की जरूरत है

यदि आप रेड न्यूज़ से जुड़ना चाहते हैं तो
कृपया अपना बायोडाटा भेजें

WHATSAPP
+91 98112 71531

APPLY NOW

More Information
www.redrosenews.com

10.वीर सावरकर ब्लॉक शर्मा कॉम्प्लेक्स शकर पुर दिल्ली 110092

Email : redrosenews.24seven@gmail.com



बालजीत सिंह (हरियाना हेड)

रेड रोज न्यूज़ की तरफ से
देशवासियों को होली की
हार्दिक शुभकामनाएं

आबादी क्षेत्र में शराब ठेकों से परेशान ग्रामीण

अमेठी (संवाददाता)। जगदीशपुर क्षेत्र के हारीमऊ के पास पुरे तुला पासी गांव में अंग्रेजी, देशी शराब और बियर की दुकानें आबादी के बीच स्थित हैं। ये दुकानें जगदीशपुर-जिला मुख्यालय रोड पर हैं। यहां से स्कूली बच्चों का आवागमन होता है।

होली पर मुंबई से बनारस के लिए दो स्पेशल ट्रेन, ट्रेन में लगेंगे 22 अतिरिक्तकोच

वाराणसी (संवाददाता)। महाकुंभ के बाद रेलवे अब होली पर्व पर लोगों को सुरक्षा के साथ उनके घर पहुंचाने की तैयारी में जुट गया है। मुंबई में काम करने वाले पूर्वांचल के लोगों को होली पर्व पर घर लाने के लिए रेलवे मुंबई से बनारस और बनारस से मुंबई के लिए दो ट्यौहार स्पेशल ट्रेन चलाएगा। ट्रेन नंबर 01053 लोकमान्य तिलक टर्मिनल-बनारस द्वि-साप्ताहिक ट्यौहार विशेष गाड़ी 12 एवं 13 मार्च, 2025 को लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 12.15 बजे प्रस्थान कर ठाणे से निकलेगी जो कल्याण जं., इगतपुरी, नासिक रोड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदन महल, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, छिवकी होते हुए बनारस पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 01054 बनारस-लोकमान्य तिलक टर्मिनल ट्यौहार विशेष गाड़ी 13 एवं 14 मार्च, 2025 को बनारस से 20.30 बजे प्रस्थान करेगी। प्रयागराज छिवकी, मानिकपुर, सतना, मैहर, कटनी, मदन महल, नरसिंहपुर, पिपरिया, खंडवा, भुसावल, जलगांव, नासिक रोड, इगतपुरी, कल्याण, ठाणे से होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचेगी।

GOSWAMI TELECOM

Deals in : All Kinds of
Mobile Accessories and Repairing etc.

Sales & Service

+91 9810200248 9810200248

kuldeepgoswami4u@gmail.com

A- 19 Ramgarh Opp. Sanjay Enclave
Opp. DDA Flat Gate No. 2, Delhi - 33



कुलदीप गोस्वामी (गोस्वामी टेलीकाम दिल्ली)

की तरफ से देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

स्वामी मुद्रक व प्रकाशक विश्वजीत शर्मा ने वंदना ऑफसेट प्रिंटर्स ए-9, सराय पीपलथला एक्स, दिल्ली - 110033 से छपवाकर जे-852, प्रथम तल, जहांगीरपुरी, दिल्ली-110033 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: महेश चंद्र redrosenews.24seven@gmail.com Regd. RNI No : DELHIN/2007/21149

MO : 9717921531

॥ कोई भी कानूनी वाद-विवाद दिल्ली न्यायालय में तय होगा ॥